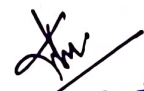


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
27.7.21	<p>कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील अपीलान्त की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्त का कथन है कि विवादित भूमि में मैं सह खातेदार हूँ। कानून सह खातेदार को अन्तरिम अर्खाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर मुझे अन्तरिम अर्खाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इसके बाद तारीख 27.7.21 को पत्र पेश की जा रही है। जबकि C.P.C. के प्रावधानों के तहत अर्खाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र का निस्तारण 01 माह के अन्दर कर देना चाहिये था। अपीलान्त निर्णय मुझे सुने बिना पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 04 शेरसिंह की मृत्यु बाद पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी, परन्तु उसे पत्रकार बना दिया। इसी प्रकार सह खातेदार किशोरी का भी देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान को पत्रकार नहीं बनाया है। इस प्रकार बाद पत्र डिफिकल्ट है। मैं विवादित भूमि का सह खातेदार हूँ। अन्तरिम अर्खाई निषेधाज्ञा की आड़ में मुझे मेरी सह खातेदारी की भूमि के उपयोग, अपना उपयोग एवं उसे हस्तांतरित करने से वंचित नहीं किया जा सकता। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः उसे अपास्त किया जावे।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलान्त की बहस तर्कों पर मनन किया। दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्त ने</p>

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	<p>बताया कि तहत अदालत में तकासमा का वाद जैरकार है। किस पत्रकार का कितने दिस्से और किस दिशा में टाइटल बनता है, इसका निर्णय तो मूल वाद में होना है। हम यहां चारा 212 आर.टी. एक्ट में पारित अन्तरिम आर्षाई निष्पेक्षा की अपील का निस्तारण कर रहे हैं। चूंकि अपीलान्त प्रसंगत भूमि का सह खातेदार है। उसे भी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। अपीलान्तीन निर्णय उसे बिना सुने पारित किया गया है। अतः उभयपक्ष की सुनवाई कर आदेश 39 नियम 3 क CPC में दिये गये समयवधि में चारा 212 का प्रा० पत्र का निस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत को निर्देशित किया जाना अन्यायोचित समझते हैं।</p> <p>अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत को निर्देशित किया जाता है कि वो चारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रा० पत्र में उभयपक्ष को सुन कर उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण C.P.C. के आदेश 39 नियम 3(क) में दी गई समयवधि 01 माह के अन्दर करे, तब तक तहत अदालत का अपीलान्तीन आदेश दि० 26.10.2020 स्थगित किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति पालनार्थ तहत अदालत को भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>